

हर किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है परन्तु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है।
- अज्ञात

कमजोरी झेल रही अर्थव्यवस्था

एक वर्ग का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है, जनवरी में मुद्रास्फीति तेजी से नीचे आ सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि करीब से देखने पर लगता है कि मुद्रास्फीति में उछाल अस्थायी प्रकृति का या किसी विशेष कारक की वजह से है।

रानी शर्मा।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आए उछाल ने पहले से ही कमजोरी झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई के जरिये जाहिर समग्र खुदरा महंगाई की दर दिसंबर में बढ़कर 7.35 फीसदी पर पहुंच गई, जो बीते छह वर्षों में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। खुदरा महंगाई के हिस्से के रूप में सबसे ज्यादा महंगाई खान-पान की चीजों में दर्ज की गई है, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12 फीसदी हो गई है। नवंबर में यह 10.01 फीसदी दर्ज की गई थी। खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी सुस्त पड़ती

अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर कर सकती है। रिजर्व बैंक के हाथ बांधने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच मुख्य ब्याज दर में कटौती करके वास्तविक ब्याज दरों को ऋणायुक्त दायरे में ले जाने का जोखिम कोई केंद्रीय बैंक नहीं उठाना चाहता। बहरहाल, मौजूदा हालात को लेकर अर्थ विशेषज्ञों की राय दो तरह की है। एक वर्ग का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है, जनवरी में मुद्रास्फीति तेजी से नीचे आ सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि करीब से देखने पर लगता है कि मुद्रास्फीति में उछाल अस्थायी प्रकृति का या किसी विशेष कारक की वजह से है। लेकिन कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि

भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल 'स्टैगप्लेशन' चरण में जा रही है। यह शब्द स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना है। जब विकास दर धीमी पड़ने लगती है, मांग में कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, और इसके समानांतर महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है तो इस अवस्था को स्टैगप्लेशन कहा जाता है। मौजूदा संकट को लेकर इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके हालात पिछले कुछ वर्षों से बन रहे हैं। लोगों के खर्च में कमी आई है क्योंकि कई सेक्टरों में छंटनी हुई है और कुछ कारोबारी संस्थानों ने अपना निवेश घटा दिया है। मांग में

गिरावट से कीमतें नीचे आनी चाहिए लेकिन तेल, दूध और सब्जियों की महंगाई इस तर्क को खारिज कर रही है। रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल पांच बार ब्याज दर में कटौती और वित्त बाजार में हजारों करोड़ रुपये के सरकारी प्रवाह का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बैंक अपने कर्ज डूबने से दबाव में हैं। कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स कटौती का लाभ मिला है लेकिन वह निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा। कारोबार में तेजी लाने के लिए ब्याज और घटाया जाए तो बाजार में पैसा बढ़ने से महंगाई और भड़क सकती है। इस तरह इकोनमी एक कुचक्र में फंस सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। वैसे ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि स्टैगप्लेशन जैसे बड़े नतीजे सिर्फ एक-दो महीनों के आंकड़ों से नहीं निकाले जाने चाहिए।



भयभीत आंखें

डॉ. अर्चिका दीदी।

जहां पर बोलना है, वहां चुप रह जाते हो।

और जहां चुप रहना है, वहां चीख मचाते हो।

जहां सिर कटे मेरे जवान का,

वहां शांतिदुत आ जाते हैं, जब आतंकी मरता है,

वहां नकली अवार्ड फिकते हैं। मिशन स्कूल के ये छात्र, सारी बकवास सुनते हैं।

अगर मां-बाप संस्कार सिखाते हैं, तो पंखे से झूल जाते हैं।

गगन चुम्बी कबाड़ की माल मे, जब खाली करते हैं।

पर शिक्षा-स्वास्थ्य के लिये, मुफ्तखोरी मांगते हैं।

सड़क जाम के काले धुंए से, हवा तबाह कर देते हो।

पर जब दम घुटता है तो, पराली को गाली देते हो।

टपोरियों-मवालियों से, प्यार जताते रहते हो। जब अपनों को प्यार देना है, वहां नाता भूल जाते हो।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

ब्याज के बंधन खोलेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अर्से बाद अपनी मुख्य ब्याज दर रीपो रेट घटाई है। सारे भारतीय बैंक इसी दर पर रिजर्व बैंक से पैसे उठाते हैं। रीपो रेट में चौथाई फीसदी यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिससे यह 6.50 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी हो गई है। आरबीआई ने अपनी ब्याज दर में कमी पिछली बार अगस्त 2017 में की थी। उसके नए गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली मौद्रिक नीति है।

पूर्व वित्त सचिव दास को बीते दिसंबर में यह जिम्मेदारी दी गई तो ऐसी अटकलें लगाई गई कि आते ही वह केंद्र की मर्जी के अनुरूप ब्याज के बंधन खोलेंगे ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी हलचल आए। चुनावी साल में लोन सस्ता होना सत्तारूढ़ दल के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन रीपो रेट घटाने को सीधे-सीधे राजनीतिक दबाव में लिया गया फ़ैसला कहना गलत होगा। छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने आम राय से नीति को सख्त से न्यूट्रल बनाने का फ़ैसला लिया। बहस सिर्फ रीपो रेट को स्थिर रखने और इसे घटाने के बीच थी और पलड़े का दूसरी तरफ झुकना लाजमी था। शक्तिकांत दास न सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लक्ष्मणों का आकलन करके ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत का रुझान स्थिर रहने या नीचे जाने का है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से क्रूड की किल्लत पैदा होने की आशंका थी, जो अमेरिका की नरमी से खत्म हो गई। अमेरिकी रिजर्व बैंक फेड ने अपनी दरें बढ़ाने को लेकर ठंडा रुख अपना लिया है, लिहाजा डॉलर भी तेजी से महंगा नहीं हो रहा। भारत समेत पूरी दुनिया में खाद्य वस्तुओं का सस्ता होना एक और राहत की बात है। चीन और दुनिया की कई और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सुस्त पड़ना एक अलग समस्या है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इस बीमारी से भी बची हुई है।

यह मैदानों के प्रदूषण से नहीं, ठेठ गंगा की जड़ गोमुख ग्लेशियर से आ रहा है और अकेली गंगा नहीं, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की बहुतेरी नदियां इस खतरे की जद में हैं।

नया नागरिकता कानून

अमर शाह।

भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी गंगा के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जी नहीं, इस खतरे का संबंध नमामि गंगे और गंगा ऐक्शन प्लान जैसी सरकारी योजनाओं की विफलता से नहीं है। यह मैदानों के प्रदूषण से नहीं, ठेठ गंगा की जड़ गोमुख ग्लेशियर से आ रहा है और अकेली गंगा नहीं, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की बहुतेरी नदियां इस खतरे की जद में हैं। 'हिंदूकुश-हिमालय असेसमेंट' नामक अध्ययन में बताया गया है कि इन दोनों पर्वतमालाओं से निकलने वाले ग्लेशियर (हिमनद) लगातार पिघल रहे हैं और इनमें से दो-तिहाई इस सदी के अंत तक खत्म हो सकते हैं। 210 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार यह रिपोर्ट काठमांडू में स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डिवेलपमेंट' द्वारा जारी की गई है।

स्टडी के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ने दिया जाए, तो भी इलाके के एक-तिहाई ग्लेशियर नहीं बचेंगे और बहुतेरी अगर 2 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसकी आशंका ज्यादा है, तो दो-तिहाई ग्लेशियर नहीं रहेंगे। दरअसल पूरी दुनिया में



हिमनदों के पिघलने का सिलसिला 1970 से ही तेज हो चुका है। इसके एक सीमा पार करते ही नदियों की दिशा व बहाव में बदलाव आ सकता है। बर्फ पिघलने से यांगत्सी, मीकांग, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के प्रवाह पर फर्क पड़ेगा और इनमें से कुछ बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी। इन नदियों पर बड़ी संख्या में किसान निर्भर करते हैं। 25 करोड़ पर्वतीय और 165 करोड़ मैदानी लोगों का जीवन इन पर टिका है।

नदी के प्रवाह में बदलाव से फसलों की पैदावार के साथ ही बिजली उत्पादन पर भी फर्क

पड़ेगा। वैकल्पिक नजरिये से देखें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक वूटर ब्यूटार्ट इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि इस मामले में अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के बाद भी नदियों को और जगहों से पानी मिल जाता है। जो भी हो, ग्लेशियर खत्म होने की बात को अब गंभीरता से लेना हमारी मजबूरी है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए चला विश्वव्यापी अभियान भी पिछले कुछ समय से ठिठका हुआ सा लग रहा है। सारे देश एक-दूसरे को नसीहत ही देते हैं। खुद अपने यहां कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर उलटा असर पड़ सकता है।

उद्योग-धंधे लगाने में पर्यावरणीय शर्तों की अनदेखी अभी हमारे यहां ही आम बात हो चली है, जबकि हिमालय का संकट सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही पहुंचाने वाला है। एक तो हमारी बहुत बड़ी आबादी हिमालय पर निर्भर है, दूसरे गंगा के बिना भारतीय सभ्यता की कल्पना भला कौन कर सकता है। अच्छा हो कि हम इस संकट के बारे में और ठोस जानकारी जुटाएं और इससे निपटने के कार्याभार को जल्द से जल्द अपने नीतिगत ढांचे में शामिल करें।

अभ्युयोग-4923

	3	7		6	2	5
3	29	6	37		31	1
1	2			5	6	
	30	1	30		31	
	6	5			3	2
2	33		31	3	30	7
6	1	2		7	4	

प्रस्तुत खेल सुवर्ण व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, पहले काले वर्ण में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्णों की संख्या का कुल योग होगा, चौथी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है।

अपना ब्लॉग अपने-अपने अभियान

प्रदीपा भारत ने अपने महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान के तहत चंद्रयान-2 को चांद की ओर भेजा हालांकि उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बीते साल इजरायल ने भी एक छोटा रोबोटिक लैंडर उस ओर भेजा था, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2023-24 तक चांद पर इंसानी मिशन भेजने को लेकर अपना काम तेज कर दिया है। अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद प्राचीन काल से ही मानव जाति की जिज्ञासा का विषय रहा है। पिछली सदी के पूर्वार्ध तक हम अपनी चंद्र जिज्ञासा को दूरबीन से ली गई तस्वीरों से ही शांत करते थे। पहली बार साल 1959 में रूसी (तत्कालीन सोवियत) अंतरिक्ष यान 'लूना-1' चंद्रमा के करीब पहुंचने में कामयाबी रहा। इसके बाद रूसी यान 'लूना-2' पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरा। सोवियत संघ ने 1959 से लेकर 1966 तक एक के बाद एक कई मानवरहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा की धरती पर उतारे।

